



04 - तारों में बहती बिजली
फिर जौँड़ेगी दिल



05 - अंतर्राष्ट्रीय माड़िना
कलाकार कौशल्या देवी
शर्मा और उनका रथना...

A Daily News Magazine

इंदौर

शनिवार, 17 अगस्त, 2024



इंदौर एवं भोपाल से एक साथ प्रकाशित

वर्ष 9 अंक 293, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रु. 2 (डाक पंजीयन संख्या: MP/IDC/1529/2016-2018)



06 - स्वतंत्रता दिवस के
मुख्य समारोह में श्री पटेल ने फहराया...



07- कलेज बंगले के
सामने तक आगया
जानवरों का जगह...

बांगलादेश

बांगलादेश

प्रसंगवश

क्या शेख हसीना पर आपराधिक मुकदमा चलाना संभव है?

तान्हा तसनीम

दि इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल (आईसीटी) ने बांगलादेश में आशक्षण विरोधी आंदोलन के संबंध में पूर्ण प्रधानमंत्री शेख हसीना समेत जौ लोगों के खिलाफ जांच करने का फैसला लिया है। सभी पर हत्या, नरसंहर और यातान के आरोप लगाए गए हैं। आशक्षण विरोधी आंदोलन के दौरान के छात्र के पिता ने बुधवार को यह याचिका लगाई थी।

अतिरिक्त सरकार के कानून, न्याय और संसदीय मामलों के सलाहकार प्रोफेसर आसिफ नजरूल ने बुधवार को कहा कि अभियुक्तों के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल में मुकदमा शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा, 'आप साफ़ तौर पर कह सकते हैं कि आईसीटी में द्राघि शुरू किया जाएगा। यह इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल में मुकदमे के तहत हम पूर्ण प्रधानमंत्री और अन्य लोग, जिन पर आरोप है, हम उन्हें काई बुधवार को बुधवार के लिए बने कानून में शेख हसीना पर मुकदमा चलाना संभव है? इस कानून में क्या कहा गया है?

बांगलादेश में जब 2008 के चुनाव हुए थे तब अवामी लीग ने वोषणात्र में कहा था कि मानवता के खिलाफ अपराध करने के खिलाफ मुकदमा चलाना जाएगा। संसदीय चुनाव जीतने के बाद अवामी लीग सरकार ने बांगलादेश के मुताबिक मुकदमे की पहल की थी। 1973 में बने इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल एक्ट के तहत अभियुक्त की जांच और मुकदमा चलाया जा

सकता है।

यह एक्ट 1971 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बांगलादेश में हुए मानवता के खिलाफ अपराधों पर मुकदमा चलाने के लिए बनाया गया था। हालांकि साल 2010 से पहले इस कानून के तहत ना तो किसी पर मुकदमा चलाया गया और ना ही किसी के सजा दी गई। साल 2009 में बांगलादेश की संसद ने 'बुद्ध अभियुक्तों पर मुकदमा' चलाने पर एक मीठाकाफ प्रस्ताव पास किया था। इसके बाद व्यक्तियों और समूहों पर ट्रिब्यूनल में द्राघि चलाने और ट्रिब्यूनल की कार्यवाही के स्वतंत्र संचालन के लिए कानून में कुछ संशोधन किए गए। इसके जारीए साल 2010 में ट्रिब्यूनल, बर्कीलों के पैनल और जांच एजेंसियों का धारा 3(1) के मुताबिक कोई व्यक्ति, समूह या संशस्प और सुरक्षा बलों से जुड़ा कोई संस्थय इस कानून की उप-धारा दो में बताए गए किसी भी अपराध में शामिल है तो उस पर आईसीटी मुकदमा चलाने और सजा देने का अधिकार रखता है। कानून के मुताबिक बांगलादेश की सीमा में गए अपराधों के लिए आईसीटी के पास यह अधिकार होगा, भले व्यक्ति या समूह किसी भी राष्ट्र से वर्त्यों ना संबंध रखता हो। मानवता और शांति के खिलाफ अपराध, नरसंहर, युद्ध अपराध, जिनेवा कन्वेन्शन के विपरीत काम करना, अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अपराध करने की स्थिति में इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल को मुकदमा चलाने की शक्ति दी गई है।

बांगलादेश सरकार के अटॉर्नी जनरल मोहम्मद

असदुज्जमां ने कहा कि इस कानून के तहत पूर्ण प्रधानमंत्री शेख हसीना पर मुकदमा चलाना संभव है। उन्होंने कहा कि 1973 का जो कानून है उसमें मानवता के खिलाफ अपराध भी उसी के अंदर आता है। इसका मतलब है कि शेख हसीना के खिलाफ अधिनियम की धारा तीन की उपाधि 2(ए) के मुताबिक मानवता के खिलाफ अपराध का आरोप लगाया जा सकता है।

इस धारा के अनुसार, हत्या, विनाश, गुलाम बनाकर रखना, निवासन, कारावास, अपहरण, यातनाएं देना, रेप, नामरिकों के खिलाफ बिए गए अमानवीय कृत्यों की सुनवाई इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल में की जा सकती है। इसके अलावा यहां राजनीतिक, जातीय या धार्मिक आधार पर उत्तीर्ण के मामलों की सुनवाई भी सकती है। राणा दासगुप्ता ने इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल में अधियोजक के रूप में दर्ज किया है। हालांकि उन्होंने 13 अगस्त को इस्तीफा दे दिया था। वे बांगलादेश हिंदू-बौद्ध-ईसाई एकता परिषद के महासचिव भी हैं।

दासगुप्ता कहते हैं, 'इस कानून का एक लंबा इतिहास है। यह 1971 के मुक्ति संग्राम के देखते ही बनाया गया था। यह कानून उन लोगों पर मुकदमा चलाने के लिए बनाया गया है जिन्होंने वहां युद्ध अपराध किए हैं।' उनका मानना है कि जिस संदर्भ में बताए जा रहे हैं, वह संबंध यहां लागू नहीं होता है। हालांकि, बांगलादेश सुनीम कोर्ट के विरिष बकील मजिल मोर्चों का मानन है कि शेख हसीना और अन्य पर मुकदमा आसानी से चलाया जा सकता है। उन्होंने कहा, 'पिछली सरकार ने जो कानून

संशोधित किया था, उसमें मानवता के खिलाफ अपराध या नरसंहर का मुकदमा चलाया जा सकता है।'

बकील का कहना है कि ट्रिब्यूनल के पास किस अपराधों के खिलाफ मुकदमा चलाने की शक्ति है, वह कानून में साक-साक लिखा गया है। उनका कहना है कि इस मामले में बहस की कोई गुंजाइश नहीं है। पाँच अगस्त को साकर में गोली लाने से अलीक अहमद सियाम नाम के एक छात्र धायल हो गया था। वे नींवों कक्षा में पढ़ते थे। धायल होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया लेकिन दो दिन बाद ही उनकी मौत हो गई। उसी के मद्देनजर पूर्ण प्रधानमंत्री शेख हसीना समेत 9 लोगों पर मानवता के खिलाफ अपराध और नरसंहर का आरोप में मामला दर्ज किया गया था। अपराध के तरीके बालबुल कबील की तरफ से सुनीम कोर्ट के वकील गजी एमएच तनीम ने इसे लेकर इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल की जांच एजेंसी में शिकायत दर्ज कराई है।

इसी दिन मीरपुर में कॉलेज छात्र फैजुल इस्लाम

राजनीति की आरोप में पूर्ण प्रधानमंत्री शेख हसीना

समेत 24 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।

इसके बाद गुरुवार को मीडिया के लिए बाजार नाम का शोभाजी दाका के शेंखगाला नगर थाना क्षेत्र मंडी शेख हसीना समेत 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। इस मामले में उन पर शब्दबूद्धीनाम के ऑटो रिक्षा चालक की हत्या का आरोप लगाया गया है।

(बीबीसी हिंदी में प्रकाशित

लेख के संपादित अंश)

यूसीसीपीएममोदीने करदिया 'खेला'

● यूनिफॉर्मसिविलकोडपरपीएमनेचलदी‘चक्रव्यूह’वालीचाल ● यूनिफॉर्मकीजगह‘सेक्युलरसिविलकोड’कहविपक्षकोउलझाया



यूनिफॉर्मसिविलकोडकाजिकाया। अब इस बात का जिक्र होने नई बात नहीं है, जौंपीजोंपर एक जातीय धारा 3(1) के मुताबिक बाल गांव के पास यह अधिकार होगा, भले व्यक्ति या समूह किसी भी राष्ट्र से वर्त्यों से कांसंध रखता हो। मानवता और शांति के खिलाफ अपराध, नरसंहर, युद्ध अपराध, जिनेवा कन्वेन्शन के विपरीत काम करना, अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अपराध करने की स्थिति में इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल को मुकदमा चलाने की शक्ति दी गई है।



सबसे बड़ी रणनीति माना जाएगा। अगर थोड़ा पीछे चला जाए तो पता चलता है कि बीजेपी का

सबसे ज्यादा हमले यह बोलकर होते हैं कि पार्टी सांप्रदायिक है, उसकी तरफ से विंड-मुस्लिम किया जाता है। इसी वज्र से जब बीजेपी ने यूनिफॉर्मसिविलकोड की बात की, विपक्ष ने तुरत इसे 'हिंदूसिविलकोड' की तरह पेश किया, दिल्लीने की पूरी कार्रवाई की सबसे बड़ी पार्टी अपने पुरुषोंने हिंदुत्वाले पंडितोंपर आगे बढ़ रही है, उसे बस मूलियों को दबाने का काम करता है। अब इस रैटेंटिव से लड़ने के लिए ही पीएम मोदी ने बड़ा बाला खेल कर दिया है। संवर्तन दिवस की स्पीच में उन्होंने जानवृक्षकर इस बाल सेक्युलरसिविलकोड का जिक्र किया है।

सेक्युलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्षता।

समृद्ध भाषा और सांस्कृतिक धरोहर को सहेजने का अवसर है भारतीय भाषा महोत्सव : मुख्यमंत्री

- मुख्यमंत्री ने सप्रे संग्रहालय की गतिविधियों को सदाहा ● सप्रे संग्रहालय की अनुदान राशि की दोगुनी ● मुख्यमंत्री ने गहोत्सव का किया शुभारंग

बोले-ज्यादा दिनों तक भारत अलग-अलग नहीं दिखेगा, बांगलादेश संकट के बीच कहा गया।

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. योहन यादव ने संग्रहालय द्वार



संक्षिप्त समाचार

राहुल की नागरिकता पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे सुब्रमण्यन स्वामी

- सरकार से ऐपशन की मांग, लगाया नरम रुख अपनाने का आरोप



नई दिल्ली (एजेंसी)। भाजपा नेता सुब्रमण्यन स्वामी ने राहुल गांधी की नागरिकता के मामले में सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। स्वामी ने पिछले बार ही आरोप लगाया था कि राहुल गांधी के पास बड़ी नागरिकता है। अब उन्होंने अदालत का रुख किया है और माम की है कि बड़े केंद्र सरकार को इस मामले में ऐपशन लेने को क्रेड। इसके अलावा कोर्ट से माम की है कि बड़े केंद्र सरकार से मेरी शिक्षायात पर रटेंटस रिपोर्ट मांगे। अगस्त 2019 में सुब्रमण्यन स्वामी ने केंद्र सरकार को पत्र लिया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी के पास बड़ी नागरिकता है और वह कांग्रेस पर धर्षण करता है। उन्होंने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9 का उद्धरण देते हुए कहा था कि वह किंसी एक देश के ही नागरिक हो सकते हैं। सिविलिन शिप एवं ट्रॉफी 1955 का जिक्र करते हुए स्वामी ने कहा था कि उनसे भारत की नागरिकता छीन ली जाहिर है। संविधान का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा था कि यदि कोई नागरिक दूसरे देश की सिद्धिजनशीलता होती है तो फिर उस भारतीय नागरिकता का त्याग करना होगा। इस संबंध में केंद्र सरकार की ओर से राहुल गांधी को 20 अप्रैल, 2019 को एक नोटिस की भेजा गया था। इस नोटिस का प्रिय था - नागरिकता के संबंध में शिक्षायात। स्वामी का कहना था कि ब्रिटेन में पॉलोकूट कूलनी बैकलाइंस लिमिटेड के राहुल गांधी निवेशकों में से एक है। उनका दावा था कि कंपनी ने सालाना रिटर्न 2005 और 2006 में फाइल किया था।

70वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स का ऐलान गया ऐलान

- मनोज बाजपेयी की गुलमोहर बैस्ट हिंदी फिल्म मर्बंड (एजेंसी)। शुक्रवार को 70वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स का नाइट्समेंट किया गया। इसमें मनोज बाजपेयी और शमिला टैगोर की फिल्म गुलमोहर को बैस्ट हिंदी फिल्म चुना गया है। कानूनी रूप से बैस्ट एक्टर और बैस्ट फिल्म के अवॉर्ड अपने नाम किए। फिल्म के लिए ऋषभ शेट्टी बैस्ट एक्टर बैस्ट एक्टर चुने गए हैं। तात्पर फिल्म तिरुचारामलम के लिए नित्या मेनन और गुरुजीती फिल्म कल्क एक्ट्रेस के लिए मानसी पारेख बैस्ट एक्ट्रेस बनी हैं। फिल्म छाँचाई के लिए बैस्ट डायरेक्टर का अवॉर्ड सुरज बड़जाता को मिला है। इसी फिल्म के लिए नीना गुप्ता ने बैस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवॉर्ड जीता है।

प्रैवेक्षक सिर्फ एटेनरी में ब्रेम्स्टर के लिए अपरिजित सिर्फ एटेनरी है। ऐ अवॉर्ड उन फिल्मों के लिए दिया जाता है जिनमें फिल्म सेसर बैर्ड ने 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2022 के बीच सेसर सर्टिफिकेट दिया है। अवॉर्ड सेरेमनी अक्टूबर 2024 में होगी। नेशनल अवॉर्ड विनर को एक मेडल की तरह राजत कमल या स्वर्ण कमल दिये जाते हैं। इसके साथ - साथ नकद प्रकाश भी दिया जाता है। कुछ कैटरगोरी में सिर्फ स्वर्ण कमल या रजत कमल ही मिलता है। पिछले साल यह अवॉर्ड अल्लू अर्जुन को मिला था।

महाराष्ट्र में चुनाव से पहले हो सीएम फेस का ऐलान



उद्घव बोले-पवार साहब और कांग्रेस जिसका नाम तय करेंगे, उसका समर्थन करेंगे।

मुंबई (एजेंसी)। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्घव ठाकरे ने शुक्रवार को कहा- चुनाव से पहले सीएम फेस का ऐलान होना चाहिए। पवार साहब और कांग्रेस नेता पृथ्वीराज जिसे भी सीएम बनाएंगे, मैं उनका समर्थन करूँगा। मुंबई में महाविकास अचाड़ी की मर्टिंग में कार्यकारीओं को संबोधित करते हुए उद्घव ने कहा कि मैं अधिकतम विधायकों वाली पार्टी को मुख्यमंत्री पदमिलने के फार्मूले का समर्थन नहीं करता। महाराष्ट्र सरकार बहानों को 1500 रुपए देने का ऐलान कर रही है, लेकिन इनकी योजनाओं का प्रचार करने के लिए 10 जनरा रुपए खर्च कर रही है। सरकार गिराने के लिए 50 खोखे और लड़की बहन को 1500

रुपए। दरअसल, महाराष्ट्र में अक्टूबर में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। इसे लेकर ही एमवीए की आज मीटिंग हुई। इसमें एनसीपी शरद गुट के चीफ शरद पवार और कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चक्रवर्ती भी शामिल हुए थे। कोरोना सरकार ने हमने काफी काम किया। इसलिए मुस्लिम के मने भय था, लेकिन मैंने उस वक्त कहा था कि देश को जो ऐसे काम करेंगे उसे जनरा नहीं देंगे। इसलिए मुस्लिम साथ आए। मान लिया जाए कि उन्होंने हिंदुत्व छोड़ दिया है। वक्फ बोर्ड ही नहीं, हिंदुओं के मंदिर के मामले में भी जांच होनी चाहिए।

आजकल कन्नौज हेडलाइन में, बीजेपी वाले मिले हुए हैं

नवाब सिंह यादव पर पहली बार बोले अधिलेश यादव



कन्नौज/लखनऊ (एजेंसी)। कन्नौज में पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव की गिरफ्तारी के बाद सत्तारूढ़ बीजेपी और विपक्ष सभा के बीच वार-पलटवार का दौर चल रहा है। एक ओर बीजेपी नवाब सिंह को सपा नेता कर रही है, वहीं सपा ने पल्ला झाड़ दिया है। सपा का कहना है कि बीजेपी विरोधी गतिविधियों के कारण नवाब सिंह यादव को सपा से निकाला जा चुका है। नवाब सिंह यादव पर नौकरी दिलाने के नाम पर 15 साल की लड़की से दुर्क्रम का आरोप लगा है। इस पूरे मामले में पहली बार सपा अधिकारी यादव ने अपना मुंह खोला है।

जो अग्नि हमें गर्मी देती है, हमें नष्ट भी कर सकती है; यह अग्नि का दोष नहीं है।

चाणक्य नीति



अस्पताल में तोड़फोड़ पर 'हाई' हुए हाईकोर्ट के तेवर

● ममता सरकार पर की सख्त टिप्पणी, बेहतर है अस्पताल बंद कर दिया जाए ● 7 हजार लोग एक साथ पैदल नहीं आ सकते, मरीजों को शिफ्ट किया जाए



कोलकाता (एजेंसी)। कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में लेडी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या की घटना के बाद अस्पताल में तोड़फोड़ पर कोलकाता हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी को बोला है कि बेहतर है अस्पताल को बंद कर दिया जाए और मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए। कोलकाता हाई कोर्ट ने कहा, यह घटना राज्य मरीजों की परी नामामी का सबल है और यह त्रैमायण स्थिति है। डॉक्टर निवार होकर काम करेंगे हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि इस घटना के बाद आप क्या कर रहे हैं। हरितायत के तौर पर क्या कदम उठाए गए थे। हाई कोर्ट में अस्पताल में हुई तोड़फोड़ और सबूत मिटाने की कोशिशों की जांच को लेकर एक याचिका दायर हुई थी। इसमें कार्यवाही की मांग की गई थी। हाई कोर्ट ने कहा कि आमतौर पर अगर लोग

अस्पताल में घुसते हैं, तो इमरजेंसी की स्थिति में भी पुलिस को बहां रहना पड़ता है लेकिन अगर 7000 लोग एक साथ अंदर आते हैं तो यह मानना मुश्किल है कि यह राज्य सरकार की विफलता नहीं है। हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर 7000 लोग आ रहे थे तो पैदल तो नहीं आ सकते, इसलिए राज्य मरीजों परी पूरी तरह से विफल हुई है। वहीं राज्य सरकार की ओर से पेश हुए बीकाने ने अदालत में कहा कि हमने स्थिति को संभाल लिया है। सरकार ने कहा कि आरोपियों की पहचान करके और उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि घटना के बाद यह सब क्यों हो रहा है। आपने पहले क्यों उस पर ध्यान नहीं दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि अगर 15 लोग घुसते हैं तो हम समझ सकते हैं, सुरक्षा में चूक हुई है।

गिरीश जोशी एमसीय कुलगुरु द्वारा सम्मानित



भोपाल। कर्मसूली माखनलाल चतुर्वेदी राणीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय भोपाल में आपकार के संस्कृत मंत्रालय के अंगतीकर्ता इंद्रिय गांधी राणीय कला केंद्र, नई दिल्ली के संस्कृत विश्वविद्यालय और राज्य विश्वविद्यालय के स्थापना विवाद में आपको बड़ी विश्वविद्यालय के नाम दिया गया।

कार्यक्रम में बरकान्साह विश्वविद्यालय के कुलगुरु, एस के जैन, मध्यप्रदेश निजी विविध परिषद एवं जल संसाधन विभाग के चूल्हाल चंद्रयांशु को बधायेंगे।

प्रथम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस हेतु नेपकास्ट द्वारा कार्यक्रमों का आगाज

मेपकास्ट एवं जल संसाधन विभाग का संयुक्त आयोजन

लैंडर मॉडलों के सौंपट लैंडिंग की प्रतियोगिता करारा गया जिसमें छात्राओं द्वारा डिजाइन कर लाए गए लैंडर ने सफलतापूर्वक अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने सफलतापूर्वक

भोपाल। विद्यार्थियों में अंतरिक्ष विज्ञान और रोकेत के प्रति आकर्षण और रोकेत का संबंध नवीन उच्चतर माध्यमिक चुनावभू

